प्रो. रामगोपाल यादव: इन सब्जैक्ट्स में टीचर हैं या नहीं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: हां, सर सब टीचर्ज़ हैं। 13 टीचर हैं और 48 लोगों की सैंक्शंड पोस्ट्स हैं 168 लड़कों के लिए 13 टीचर्ज़ भी हिन्दुस्तान के किसी भी नॉर्म से अधिक हैं, लेकिन 12 फैक्लटी यहां एडज़ंक्ट फैक्लटी है, विज़िटिंग प्रोफेसर्ज हैं। इसलिए 25 लोग नियुक्त हैं। अध्यापकों की संख्या में कोई कमी नहीं है। 168 छात्र हैं। इसलिए आपने अगर मेरा पहला उत्तर सुना होता तो मैंने तभी बता दिया था कि हमने 48 पोस्ट्स सैंक्शंड की हैं जिसमें से 13 इन्होंने भरी हैं। 25 आस-पड़ोस के विश्वविद्यालयों से बुलाते हैं और इस तरह से फैक्लटी में कोई कठिनाई नहीं है। दिक्कत है तो छात्रों के आने में दिक्कत है। जैसा सम्मानित सदस्य ने बताया था कि होस्टल की कमी के कारण छात्र कम आते हैं। भवनों की कमी होने के कारण से कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। और जैसे-जैसे भवन बढ़ेंगे, छात्रावास बढ़ेंगे, वैसे-वैसे कैपेसिटी भी बढ़ेगी। विश्वविद्यालय ग्रो करते हैं।

Vacant posts of teachers in engineering colleges

*442. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 10,000 teachers' posts are going abegging in engineering colleges around the country;

(b) if so, since when these posts are lying vacant and what are the reasons therefor; and

(c) what steps Government have taken to fill up the vacant posts and by when?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) It is estimated that shortage of teachers of this order of magnitude exists in engineering colleges at various levels. There has been a major expansion of the technical education system in the recent past and it takes time for recruitment of sufficient number of teaching personnel as it is a time consuming process. Filling of vacancies is a dynamic and continuous process. One of the main reasons for vacancies is the relative disinclination of competent professionals to join the teaching profession in view of generally better opportunities available elsewhere. Government has taken various steps, *viz* revision of pay scales along with better service conditions, launching of Early Faculty Induction Programme to attract young talents to the teaching profession; and operation of various faculty development programmes like, quality improvement programmes, continuing education programme, etc. to retain existing teaching faculty.

श्री संजय निरुपम: आदरणीय सभापति महोदय, किसी भी समाज में शिक्षक की कमी हो जाए तो उस समाज के लिए उस से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। महोदय, स्वयं माननीय मंत्री जी एक शिक्षक रहे हैं, इस नाते वह समझ सकते हैं। अब माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह तो बस ऐसे हो गया कि चलो कुछ लिखकर दे दो। महोदय, बड़े साफ-साफ शब्दों में पूछा गया है कि क्या 10 हजार शिक्षकों की कमी है, लेकिन उत्तर से साफ-साफ आंकड़ा नहीं आ रहा है। फिर कब से यह कमी महसूस की गयी, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। महोदय, सब से पहले तो मेरे मूल-प्रश्न का बड़े विस्तार से जवाब दिया जाये। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए टैक्नीकली एक्सपर्ट मेनपावर बहुत जरूरी होती है और उसे प्रोड्यूस करने के लिए, डवलप करने के लिए टैक्नीकल टीचर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे यहां टैकनीकल टीचर्स की कमी पड़ रही है। यह कमी क्यों पड़ रही है, इस बारे में माननीय मंत्री महोदय ने हल्का सा रिफरेंस दिया है। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश के छात्र इंजीनियर तो बनना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियरी पढ़ाना नहीं चाहते। हमारे देश में हर साल लगभग दो, ढाई लाख इंजीनियर्स तो तैयार होते हैं, लेकिन पोस्ट-ग्रेजुएट एजुकेशन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 7 हजार से भी कम है। दूसरा कारण यह है कि हमारे देश से प्रतिभा का पलायन हो रहा है और सब से ज्यादा आई.आई.टीज. जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से इंजीनियर बनकर निकलने वाले छात्र बाहर जा रहे हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट सवाल है कि ऐसी प्रतिभाओं के पलायन को रोकने की दिशा में आप का ठोस प्रयास क्या है? साथ ही यह कि जैसे आप ने कहा है कि प्रोफेसर्स की नौकरी में सेवा शर्तों को बेहतर बनाया जा रहा है, मैं जानना चाहूंगा कि आप उन्हें किस तरह से अच्छा बना रहे हैं? उन को ज्यादा-से-ज्यादा आकर्षित करने के लिए, अच्छी स्कॉलरशिप देने के लिए, अच्छी फेलोशिप देने के लिए भारत सरकार कौनसी व्यवस्था कर रही है? मैं चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था के बारे में बताइए जो सिर्फ कागज पर न हो।

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह बात सच है कि 10 हजार के लगभग रिक्तियां इंजीनियरिंग अध्यापन में मौजूद हैं और ये निरंतर कई वर्षों से चली आ रही हैं। महोदय, होता यह है कि कुछ लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर जगह मिलती है तो वहां चले जाते हैं और रिटायर्ड हो जाने के बाद भर्ती करने में थोड़ा सा विलंब होता है क्योंकि उन की भर्ती करने की एक प्रक्रिया है। लोग मिलते नहीं हैं, यह बात सच है। इस के लिए कुछ कार्यक्रम पिछले दो वर्षों से चलाए गए हैं, उस में एक कार्यक्रम यह है कि हम शुरू में जब छात्र एम.टेक. के लिए आते हैं तो सेमिस्टर में ही हम उन को कह देते हैं कि आप को हम 10 हजार रुपए महीना स्कॉलरशिप देंगे। आप आगे आइए, जब तक आप पढ़ाते रहेंगे, आप को 10 हजार की स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, शर्त यह है कि इस के बाद आप को तीन साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा। महोदय, यह संख्या जैसे ही उपलब्ध होगी काफी बड़ी संख्या उस में दी जा सकेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 हजार के करीब अर्जियां विचार के लिए आई हैं। धन के अभाव के कारण हम इस में से एक हजार भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम

जितना अधिक धन इस दृष्टि से दे सकेंगे, इन लोगों को अच्छे अध्यापन के लिए आगे बढ़ा सकेंगे। महोदय, इस के अलावा हम ने यह भी कोशिश की है कि अन्य स्थानों से भी अध्यापक वहां लाए जाएं। इंडस्ट्रीज से अध्यापक वहां आएं, पढ़ाएं और जाएं। हम कॉलेजेज के लोगों को भी कह रहे हैं कि अगर वह अपनी योग्यता में सुधार करते हैं, गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पी.एच.डी. की डिग्री लेते हैं तो उस के लिए भी उन्हें पैसा दे रहे हैं। यहां तक व्यवस्था की गई है कि जहां वह पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ाते रहें, वेतन लेते रहें, लेकिन पी.एच.डी. होने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम उन को पूरी स्कॉलरशिप देंगे, पूरा वजीफा देंगे। महोदय, ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन का असर होगा जो कि आप को अगले साल या उस के अगले साल से पता चलना शुरू होगा। महोदय, एक कारण यह भी हुआ है कि इंजीनियरिंग और अन्य विषयों की शिक्षा में तेजी से हमारे देश में विस्तार हुआ है। हर साल 15-20 प्रतिशत के बीच में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज में इनटेक बढ़ रहा है, भर्ती बढ़ रही है, लेकिन इतनी जल्दी नए अध्यापक तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए थोड़ी कठिनाई अभी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कठिनाई को जल्दी-से-जल्दी दूर करें। महोदय, हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इनफॉर्मेशन टैक्नॉलोजी की सहायता से एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अच्छे अध्यापक के कार्यक्रम दूसरे विश्वविद्यालय में भी जा सकें। महोदय, जैसे-जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेज में यह एक्टिविटी बढ़ रही है वैसे-वैसे हम वर्चुअल क्लास का भी उपयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी अध्यापक तैयार किए जाएं। इस के लिए भी हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अच्छे अध्यापक नहीं बना पाए तो हमारी इनफॉर्मेशन टैक्नॉलोजी का जो स्तर है, वह आने वाले वर्षों में बहुत गिर जाएगा और इस मामले में हमारी दुनिया में जो साख है, उस पर भी एक बिंदु आएगा कि इन की साख गिर रही है, इन का स्तर गिर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में बहुत सचेष्ट है। हम ए.आई.सी.टी. से निरंतर चर्चा करते हैं, इंजीनियरिंग के अध्यापकों से बात हो रही है। सरकार ने अभी एक टास्क फोर्स बनाई है, कल भी उसकी एक बैठक हुई थी, उसमें मुख्य मंत्री भी शामिल हैं, केन्द्र सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, जिसके माध्यम से हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस बढ़ती हुई भर्ती की संख्या को हम आग आगे बढ़ाएं और अच्छे अध्यापक तैयार करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और मैं विनती करूंगा कि इस मामले में अगर कोई सुझाव किसी भी माननीय सदस्य के पास हों तो वे बताएं और भेजें कि हम अच्छे अध्यापकों को कैसे जल्दी तैयार कर सकते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, मंत्री जी ने ए.आई.सी.टी. - आल इंडिया काउंसिल फार टैक्निकल ऐजूकेशन - का जिक्र किया और कहा कि वे उसके सम्पर्क में हैं। ए.आई.सी.टी. ने विशेषकर पोस्ट ग्रेजुएट ऐजुकेशन में जो लगातार गिरावट आ रही है, पिछले साल उस संबंध में एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की गई थीं और बहुत सारी सिफारिशें की गई थीं। एक चिंता यह थी, उस रिपोर्ट का ही यह कहना है जिस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान

आकृष्ट करना चाहता हूं:- In the past three years, nearly 90 per cent of M.Tech students, that is, 243 out of 273 students, have quit their parent discipline to join the I.T. Industry. लगातार लोग आई.टी. इंडस्ट्री की ओर जा रहे हैं, पढ़ने में और पढ़ाने में उनका इंटरेस्ट नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में ए.आई.सी.टी. ने जो सिफारिशें दी हैं, उनके बारे में अगर माननीय मंत्री जी कुछ बताना चाहें तो बहुत अच्छा हो। उसमें विशेषकर उनका यह कहना था कि जो आप स्कॉलरशिप कह रहे हैं 10,000 की, तो उन्होंने 20,000 या 25,000 तक की स्कालरशिप के लिए सिफारिश की थी, तो उस स्कॉलरशिप के बारे में क्या करने जा रहे हैं?

आखिर में मैं यह पूछना चाहूंगा कि सचमुच में मंत्री महोदय क्या एक पूरे वादे के साथ बता सकते हैं कि शिक्षकों के लिए इंजीनियरिंग कालेजों में जो खाली जगह हैं, उनको कब तक भर दिया जाएगा?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, जहां तक स्कॉलरशिप की मात्रा बढ़ाने का सवाल है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें कितना धन मिलता है, यह तो साधन पर निर्भर करता है। हम जरूर चाहंगे कि अच्छी से अच्छी छात्रवृत्तियां हम अपने इंजीनियरों को दें, अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम उनको दें, लेकिन देश के जितने साधन हैं उनके अंतर्गत ही हमें काम करना पड़ता है। हम तो बराबर वित्त मंत्रालय से और प्लानिंग कमीशन से मांग कर रहे हैं कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए और शिक्षा के खर्च को बढ़ाया जाए तथा इस समय आप इसे खर्च न समझें, इन्वेस्टमेंट मानें। ये सब बातें हम कर रहे हैं। लेकिन आज जितने साधन हैं और जैसा मैंने आपको बताया है कि उसमें 10,000 का स्कॉलरशिप भी हम पूरे लोगों को दे पाने में समर्थ नहीं हैं, 25,000 और 30,000 रुपए स्कॉलरशिप देना आज की स्थिति में कठिन है। लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि हम इस तरफ आगे बढ़ें। हम बहुत से कारपोरेट हाउसिस से भी सम्पर्क करना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि वे फाउंडेशन्स बनाएं और इस तरफ लोगों को आगे लाने की कोशिश करें।

जिस तेजी से इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर और आई.टी. के लोगों का विस्तार हो रहा है, भर्ती का विस्तार हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, यह कहना बहुत मुश्किल है कि ये रिक्तियां कब तक पूरी की जा सकेंगी। जैसे-जैसे भर्ती बढ़ती जाएगी, इनटेक बढ़ता जाएगा, कमी बराबर बनी रहेगी, इसको पूरा करने के लिए हम चेष्टा करते रहेंगे। किसी संस्था में, किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी समय शत-प्रतिशत रिक्तियां नहीं भरी जा सकतीं, कभी न कभी कमी रहती है - लोग आते हैं, जाते हैं, रिटायर होते हैं, बेहतर जगहों पर जाते हैं। इसलिए यह एक डायनेमिक, गतिशील प्रक्रिया, है - भर्तियां होती रहती हैं, अध्यापक नियुक्त होते रहते हैं, वे जाते रहते हैं, आते रहते हैं। इसलिए यह कोई भी नहीं कह सकता कि किसी निश्चित दिन पर किसी भी संस्थान में कोई जगह खाली नहीं रहेगी।

श्री संजय निरुपम: आपने यह निर्धारित किया हुआ है कि आने वाले 2002 तक हमारे देश में जितने भी इंजीनियरिंग कालेज हैं, उनमें जो इनटेक है, जो भर्तियां हैं, उनको आप तीन गुना करने

जा रहे हैं। अगर आप भर्तियां तीन गुना करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उस हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति भी...

MR. CHAIRMAN: This is your third supplementary. So it is not allowed.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, as regards the replies that have been given, if I am to put the same question in the next Session, even then the answer would be the same. Sir, I seek your protection. So far as the Members are concerned, we make efforts to frame out questions in Part (a), (b) and (c), but the replies are generalised. In Part (b), the question was: "Since when are these posts lying vacant?" Now this has remained totally unanswered. In part (c), the Member had asked: "By when are these posts going to be filled up?" The answer is: "The posts are still lying vacant". I think there should be some efforts on the part of the Ministry to reply pointedly to the questions. The only thing which I would like to know from the Minister is whether any efforts are being made to employ or, at least, utilise, the people who are engaged in this industry, both in the public sector and in the private sector, as part-time professionals. If so, how much percentage of these lost educational hours can be made up, if these people are put? I know, in certain places, employers take objection to such employees going and giving part-time teaching these universities and engineering colleges. Would the hon. Minister make some efforts in this direction.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, we have made efforts for creating adjunct faculty. I have said that we are inviting people from industry and other colleges to come and share this responsibility and there are people who come. We want to increase this integration more and more. This forging of a sort of interface is going on. What we would like is that there should be a frequent interaction between the industry and the technological institutions so that it is beneficial to both. This is one of our methods. I have already replied that the adjunct faculty is being created. This is there in several institutions. The teachers of these institutions go for consultancy in the industry. There is a mutual interchange of academic and industrial experience. This is there and we will certainly like more and more participation of well-qualified people. We also have courses to improve the qualifications of persons with lesser qualifications coming from different colleges, who want to come and teach in these colleges. But, as you have said, the intake in going to be higher; and we are seriously thinking about it. A task force has been created by the hon. Prime Minister to

go into all these questions, and we are seriously attempting to cope with this requirement of teachers. But nobody can say, no Government can say from which date these vacancies will be filled up, because this is a dynamic process. On any appointed day, you can't tell me that all the positions have been filled up. There are vacancies that exist from times immemorial. I know that many posts are vacant; they are filled up and some more posts become vacant. So, nobody can say when there will be that day when all the posts will be filled up. This is a very dynamic and a very crude process. It is almost impossible to forecast it.

श्री ललितभाई मेहता: सभापति महोदय, देश के कई भागों में इंजीनियरिंग कालेजों में सैल्फ-फाइनेंसिंग कालेज भी अब शुरू हो गए हैं और इन इंजीनियरिंग कालेजों में जो भी ब्रांच शुरू होती है-मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें ए.आई.सी.टी.ई. की नॉर्म्स यह रहती हैं कि आपको उस.पर्टिकुलर ब्रांच में प्रोफेसर की वैकेंसी भरनी है और प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, वह पी. एच. डी. की है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लियाकत रखी गई है, वह भी पी.एच.डी. की है। पी.एच.डी. न किए हुए कई उम्मीदवार मिल रहे हैं लेकिन पी.एच.डी. की क्वालिफिकेशन न होने के कारण उनकी भर्ती नहीं की जा सकती और उस कालेज को रिकॉगनिशन नहीं दिया जा सकता। इसी कारण इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ए.आई.सी.टी.ई. अपनी नॉर्म्स में थोड़ा ढील देने पर विचार कर रही है? यह अनुपात जो आपने रखा है कि आप एक प्राध्यापक लेंगे, दो सहायक प्राध्यापक लेंगे और चार व्याख्याता लेंगे, इस तरह सात लोग आप एक ब्रांच में 60 विद्यार्थियों के लिए लेंगे। यानी टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो 8 और 9 के बीच आता है और प्रैक्टिकल जो कराने हैं, उसमें टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 15 के करीब आता है। अगर यह अनुपात घटाने पर आप विचार करेंगे तो शिक्षकों की भर्ती में जो यह प्रॉब्लम आ रही है कि योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, उसमें भी कमी आ सकती है। क्या इसके बारे में मंत्री महोदय विचार करेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, यह सुझाव कई ओर से आया है और ए.आई.सी.टी. इस पर विचार कर रही है कि इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए और समाधान कैसे ढूंढा जाए। टास्कफोर्स के सामने भी यह प्रश्न आया है और इस पर चिंता की जा रही है कि इसका क्या समाधान निकाला जाए ताकि एजुकेशन की क्वालिटी भी न गिरे, अध्यापकों की क्वालिफिकेशन भी बनी रहे और छात्रों के लिए आवश्यक संख्या में अध्यापक भी उपलब्ध रहे। यह प्रयास किया जा रहा है किस तरह से एक रास्ता निकाला जाए जिससे दोनों चीजें हम कर सकें क्योंकि अगर कम योग्यता वाले अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा तो उसकी भी अपनी कठिनाइयां हैं। उससे इंजीनियरिंग और आई.टी. टेक्नोलॉजी के हमारे जो आने वाले छात्र हैं, उनकी गुणवत्ता गिरेगी और दूसरी तरफ आज की स्थिति में अच्छे और योग्यता प्राप्त अध्यापकों का मिलना कठिन हो रहा है। इसलिए दोनों

के बीच में से रास्ता निकालने का सुझाव आया है और ए.आई.सी.टी. जब इस पर निर्णय कर लेगी तो उसके अनुसार आगे स्कीम बनाई जाएगी।

MR. CHAIRMAN: Shri Prem Chand Gupta.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, my question has already been answered. Therefore, I don't want to put any question.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Shri Gandhi Azad.

श्री गांधी आज़ाद: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कालेज में देश भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की कुल कितनी संख्या है और कितना बैक-लॉग है और उसे पूरा करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है और कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: इसके लिए तो अलग से नोटिस चाहिए, क्योंकि यह इससे उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन इन सब इंजीनियरिंग विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में और छात्रों की भर्ती के मामले में जो सरकारी आरक्षण की नीति है वह आरक्षण की नीति बराबर सतर्कता से पालन की जाए इसके आदेश हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अध्यापकों के मामले में भी जहां-कहीं कमी हो उसको पूरा किया जाए। छात्रों के मामले में तो लगभग कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती लेकिन अध्यापकों की संख्या में कई स्थानों पर कमी है क्योंकि पिछले वर्ष आयु सीमा बढ़ जाने के कारण दो वर्ष से रिक्तियां कम हुई हैं और इसलिए कुछ भर्तियों में कमी हुई है।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि देश में राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं और केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों को कितना लाभ मिला है?

श्री सभापति: यह सवाल इस सवाल से नहीं उठता है।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल: अभी जो यह प्रकरण चल रहा है इसमें सभी लोगों ने यही मुद्दा पूछा है... (**व्यवधान**)

MR CHAIRMAN: No, no. Your Supplementary does not arise out of this question. You are going off the track. (*Interruptions*) Nothing will go on record (*Interruptions*)

श्रीमती जमना देवी बारूपाल:*

श्री सभापति: उसके लिए आप दूसरा सवाल कीजिए, यह सवाल इससे नहीं उठता है।

*Not recorded.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, her question is regarding the vacancies which are there in the engineering colleges of Rajasthan.

MR. CHAIRMAN: No, no. She is putting a question about Kendriya Vidyalayas.

(Interruptions)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: She is asking about Kendriya Vidyalayas.

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं। पहली बात यह है कि दस हजार के करीब वेकेंसीज हैं। सभापति महोदय, यह संख्या बहुत बढ़ी है और यह पिछले कई वर्षों की एकुमुलेटिव फिगर्स लगती है। इसका समाधान माननीय मंत्री को करना चाहिए। मेरे प्रश्न का 'क' भाग है कि क्या इस प्रकार की जो वेकेंसीज पिछले समय से बढ़ते-बढ़ते दस हजार हो गई तो आपको नहीं लगता कि अगले आने वाले सालों में जबकि विद्यालय बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कालेज बढ़ रहे हैं उस हालत में यह वेकेंसीज की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी बजाय कम होने के। मेरा दूसरा 'ख' भाग आपने स्वयं कहा है कि पे-स्केल रिवाइज होने हैं और जब तक पे-स्केल रिवाइज नहीं होंगे तब तक अच्छे अध्यापक इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि अन्यत्र क्षेत्रों में आज ज्यादा लोगों की एम्पलोयमेंट होने लगी है क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा अच्छे वेतनमान मिलने लगे हैं, उन्हें अधिक सुविधा मिलने लगी है सरकारी क्षेत्रों से। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वेतनमानों का जो निर्णय है वह आपको कम्पेरेटिव स्टडी करने के बाद करना चाहिए अन्यथा फिर आप जो निर्णय करेंगे वह फिर से पुराना पड़ जाएगा और फिर आपको दोबारा निर्णय लेने के लिए कई वर्ष लगेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वेतनमानों का निर्णय करें। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वेतनमानों का निर्णय करते समय कम्परेटिव स्टेटमेंट बनाने का क्या आप कष्ट करेंगे ताकि आप इंजीनियरिंग कालेज के शिक्षकों के वेतनमान और सुविधाएं उसी प्रकार की बना सकें जिस प्रकार से अन्यत्र प्राइवेट सेक्टर में आजकल दी जा रही हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, लगभग 10 हजार शिक्षकों की कमी है। हमारे अध्यापकों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे यह 20 प्रतिशत कम है। एस्टिमेट कमेटी ने 1977–78 में इस मामले का अध्ययन किया था और रिपोर्ट दी थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने वैकेंसीज की स्थिति 21.45 परसेंट बताई थी, फिर डोगरा कमेटी ने 1987 में अध्ययन किया और वैकेंसीज की स्थिति 22.29 परसेंट बताई थी। डीएसटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1993 में तैयार हुई और उसने वैकेंसीज की स्थिति 17.8 परसेंट बताई थी। अगली स्टडी 1992-93 में हुई और उसने भी बताया कि ओवरआल परसेंटेज जो वैकेंसीज की है वह 19.8 परसेंट है। इसलिए यह 20 प्रतिशत की कमी हाल ही में एक्युमलेट हुई है, ऐसा नहीं है। यह इस क्षेत्र का एक फीचर है, अभिलक्षण है कि इसमें इतनी मात्रा

में वैकेंसीज रहती हैं। आज अध्यापकों की संख्या बहुत बढ़ गई है इसलिए उसका 20 प्रतिशत भी 10 हजार हो गया है। लेकिन परसेंटेजवाइज इसमें 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है। यह एकुमलेटिड संख्या नहीं है। यह इस सेक्टर का एक विशेष फीचर है। माननीय सदस्य ने जैसा इसका कारण बताया है कि इंडस्ट्री से इसका संबंध होने के कारण बहुत से लोग इंडस्ट्री में बेहतर सेवा-शर्तें मिलने के कारण वहां जाते हैं। यहां जो भी पे-स्केल्स हैं वह पंचम वेतन आयोग के साथ लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। पंचम वेतन आयोग की सिफारिश के बाद जब देश भर में सारे पे-स्केल्स का पुनर्निर्धारण होता है तभी इनका भी पुनर्निर्धारण होता है और यह कोशिश करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा-सा बेहतर बेनीफिट मिल सके इसका भी प्रयास करते हैं। लेकिन आज के दिन उस स्तर पर तनख्वाहें देना जिस स्तर से उद्योग में लोगों को मिल रही है, मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। यह भी ठीक है कि जो तनख्वाहें और जिस प्रकार की स्थिति उनकी हैं उसमें सुधार होना चाहिए। कुछ विद्यालयों में, कुछ कालेजों में हम कंसल्टेंसी की सुविधा देते हैं, आईआईटीज वगैरह में साल में 52 दिन कंसल्टेंसी कर सकते हैं और जितनी तनख्वाहें उनको मिलती हैं, उतनी ही अर्निंग वह कंसल्टेंसी से भी कर सकते हैं। इस प्रकार की योजनाओं के बारे में टास्कफोर्स और एआईसीटीई के साथ चर्चा हो रही है कि हम कैसे इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोक सकें और कैसे उनकी उन्नति के लिए क्वालिफिकेशन्स को सुधारने के लिए हम मौका दे सकें।

जल संसाधनों का औद्योगिक प्रदूषण से बचाव

443. **श्री विजय सिंह यादव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संसाधनों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो रहे पानी की मात्रा का कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 प्रदूषण से जल संसाधनों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण समिति (पी.सी.सी.) तथा पूरे देश के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। बहि:स्राव छोड़ने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा एस.पी.सी.बी./ पी.सी.सी. की सहमति लिया जाना अपेक्षित है और तत्पश्चात् इस सहमति का आवधिक रूप से नवीकरण किया जाना होगा।